ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question Hour. Question No.21.

Inordinate delay in the despatch and delivery of Postal Articles

*21. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of COMMUNICATION be pleased to state:

(a) the reasons for the inordinate delay in the despatch and delivery of postal articles, including letters and money orders, in recent years; and

(b) the measures proposed to ameliorate the situation?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

हालांकि, डाक सामान्यतः मानदंडों के अनुसार वितरित की जाती है, लेकिन विभिन्न कारणों से विलम्ब हो ही जाता है जैसे बसों, रेलों का चलना और हवाई जहाजों की उड़ान का रद्द हो जाना/देरी से चलना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूस्खलन तथा कारपोरेट डाक, शुभकामना डाक आदि का अप्रत्याशित रूप में भारी मात्रा में प्राप्त होना। कुछ राज्यों में राज्य सड़क परिवहन की बसों तथा प्राइवेट बसों द्वारा डाक लाने-ले-जाने में भी कठिनाइयां पेश आती हैं। बड़े शहरों और नगरों में, विशेष रूप से नई विकसित हुई कॉलोनियों और उपनगरों में भी डाक-वितरण, वितरण कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण दबाव में है। तथापि, अतिरिक्त कार्य को, जहां तक संभव होता है, कर्मचारियों की पुनः तैनाती करके निपटाया जा रहा है। मनीआर्डरों के भुगतान के संबंध में स्थिति सामान्यतः संतोषजनक है। तथापि, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ डाकघर कभी-कभी मनीआर्डरों का भुगतान नहीं कर पाते क्योंकि स्थानीय बैंक इस स्थिति में नहीं हैं कि वे डाकघरों को पर्याप्त धनराशि प्रदान कर सकें और कम राशि के ड्राफ्ट तैयार करने में उन्हें कठिनाई होती है। जिन मामलों में मूल मनीआर्डर ट्रांजिट में गुम हो जाता है, उनमें डुप्लीकेट मनीआर्डरों का भुगतान करने में भी विलम्ब हो जाता है। विभाग ने डाक और मनीआर्डरों के प्रेषण और वितरण में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। ये हैं:—

—छंटाई में तेजी लाने के लिए बम्बई और मद्रास में मशीन के अनुकूल डाक की छंटाई पत्र-छंटाई मशीनों पर की जाती है।

—थोक में पोस्ट की गई डाक के मामले में, मेलर्स की डाक की पहले ही छंटाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि ऐसी डाक को गंतव्य स्थान तक शीघ्र भेजा जा सके।

—जून से दिसम्बर तक के व्यस्त सीजन में पोस्ट की गई कॉरपोरेट डाक और त्यौहारों की शुभकामनाओं से संबंधित डाक की छंटाई और प्रेषण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

—प्राथमिकता के आधार पर मेल प्रोसेसिंग को युक्तिसंगत बनाना और विभिन्न श्रेणियों की डाक के समय संबंधी महत्व को ध्यान में रखते हुए उसका पृथक-पृलथक निपटान।

—निरीक्षण अधिकारियों द्वारा डाकघरों तथा आर एम एस कार्यालयों के नियमित विजिट्स द्वारा विभिन्न स्तरों पर मेल मूवमेंट तथा मेल प्रोसेसिंग की मॉनीटरिंग करना। टैस्ट लेटर पोस्ट करके डाक कार्यकुशलता का परीक्षण करना तथा लाइव मेल के ट्रांजिट समय की आवधिक जांच करना।

—मनीआर्डरों के भुगतान की, विशेषकर गांवों में, नियमित जांच और मनीआर्डरों के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

—जिन गांवों की डाक आती है, उनमें डाक का हर रोज वितरण किया जाता है जो मौसम और प्रचालन संबंधी दबावों पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संग्रहण तथा वितरण नेटवर्क की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है।

·डाक और मनीआर्डरों के पारेशण और वितरण की विभिन्न स्तरों पर निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और पुनरीक्षा के उपरान्त डाक के रूट में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है।

—पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के डाकघरों में मनीआर्डरों के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

SHRI ASHOK MITRA· Sir, I do not want to be in an accusatory mood. But, at the same time, I cannot quite ignore the immense national tragedy that is happening around the country. We call ourselves a 'Socialist Democratic Republic' and we have pledged ourselves to serve the cause of the poor. The bulk of our poor live in the countryside and many of them, millions of them, depend on letters and remittances from their relatives who serve in urban areas. Despite all that is written in this sheet of paper, it is our experience that millions of postal articles are lying in heaps, for weeks on end, in differnt depots, rail stations and so on. I want a very specific question to be answered by hon. Minister. We talk about basic services to the people of the country. Could we take a pledge, will the Government take a pledge, that in this format of basic services, they would also include the service of reaching postal communications and articles to the nation's poor? Now let me mention something else in this connection.

MR. CHAIRMAN: Please put your question. *(Interruption)*. You have made a general statement, not put a particular question. You want to know whether it would be included in the Common Minimum Programme.

SHRI ASHOK MITRA: I have put a very specific question whether in the corpus of 'basic services' they are willing to include ensuring a speedy and fast communication system for the country's poor.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमारे यहां डाक व्यवस्था संतोषजनक है इसलिए हमारे यहां शिकायतों की जो फिगर है वह बहुत ही कम है। अनरजिस्टर्ड मेल मे .0001 परसेंट शिकायते मिली हैं। रजिस्टर्ड मेल मे .1024 शिकायते हैं। मनिआर्ड्रस में .27 शिकायतें हैं। रजिस्टर्ड पार्सल मेल में 077 शिकायते हैं।

श्रीमन् इसके अलावा भी उसको इम्प्रूव करने के लिए और मोडर्नाइज करने के लिए हमने दस प्वाइन्ट एक्शन प्लान भी बनाया है 100 डेज में। उसको एचिव करने के लिए डिपार्टमेंट के आफिसर्स को आदेश भी दे दिये हैं। सुधार की आवश्यकता तो निरन्तर प्रक्रिया है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि उसकी सेवाएं बेहतर है।

SHRI ASHOK MITRA: Sir, the very fact that the Government have introduced a Speed Post System is an acknowledgement of the fact that things are not satisfactory along the normal channel. Otherwise, there would have been no necessity for such a Speed Post System. I would ask the Minister to put his hand on his heart and say that in a country where more than 80 per cent of the population have an annual income of less than five thousand rupees, it is fair to say that I will reach your destination later within the next 24 hours or 48 hours if you are willing to pay forty-five rupees. I think this is scandalous and I would specifically ask the Minister whether he would agree to reduce this fee for Speed Post articles specially where the poor in the country are in need for sending such letters.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, जितनी डाक सेवाये हमारे यहां है, वह जितने सस्ते दामो पर उपलब्ध है, वह शायद इसी देश में है। करीब 500 करोड़ का सरकार घाटा उठाकर गरीब लोगों के लिए जैसे पोस्ट कार्ड है जो कि 15 पैसे का है जब कि इसकी लागत करीब-करीब 1.85 रुपया है। **(व्यवधान)**... आप लोगों की सहमति से यह काम करना पडेगा। .**(व्यवधान)**.. लेकिन फिर भी लोगों को समय से डाक सेवायें उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। मनीआर्डरों

को वीलसेट से कई स्थानों पर भेजा गया है। और भी मार्डनाइजेशन का हमारा प्लान है और हमने पहले ही बताया है कि 10 प्वाइंट ऐक्शन प्लान 100 डेज मे अचीव करने के लिए जो बनाया है, उसको हम आप सब लोगों के सामने रख देंगे।

SHRI ASHOK MITRA: I am sorry on such routine answers

SHRI AJIT P.K. JOGI: Sir, it apperars that Mr. Mitra has lost his sharpness

श्री रामजीलाल: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर मे बताया है कि डाक सामान्य मानदंडों के अनुसार वितरित की जाती है, लेकिन विभिन्न कारणों से विलम्ब हो ही जाता है, हवाई जहाज आदि लेट हो जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हवाई जहाजों के कारण विलम्ब हो जाता है, लेकिन दिल्ली से हिसार चार घंटे मे बस पहुंच जाती है, रेल पहुंच जाती है। तब भी, मेरी खुद की डाक एक एक हफ्ते, मैं पार्लियामेंट मेम्बर हू, एक एक हफ्ते लेट हिसार में मेरी डाक पहुंचती है। हिसार बड़ा शहर है वहा दोनों टाइम डाक बांटी जाती है। आपने यह भी कहा है कि गांवो में प्रत्येक दिन डाक बांटी जाती है, यदि बात ठीक है लेकिन देखिए कि कहां इसमे कमियां हैं। डाक जो यहां से चलती है वह देर से जाती है या उसमें आगे देर होती है। इसका पूरा पता करके बतलाइए कि क्या वजह है जो डाक लेट पहुंचती है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् लेट होने के बहुत कारण हैं। हमको कहीं कहीं परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। राज्य सड़क परिवहन राज्य सरकारों से संबंधित होती हैं, इसलिए उसमें कहीं कहीं दिक्कतें आती हैं। कहीं हवाई जहाज लेट हो गया, उससे भी देरी हो जाती है। ट्रेन मे भी कभी कभी देरी हो जाती है, उसकी वजह से भी लेट हो जाती है लेकिन नार्मली 70 फीसदी डाक जो है वह समय से पहुंच रही है। 30 फीसदी के लिए मैं मानता हूं कि उसमें विलम्ब हो रहा है। उसको सुधारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

SHRI K.R.MALKANI: Sir, I am surprised to hear from the hon Minister that he is satisfied with the postal services. He said: सन्तोषजनक है। उन्होंने परसन्टेज कोट किया Percentages can be very, very deceptive. Let him come out with the exact figures. How many lakhs of complaints are there? How many lakhs of letters are lost? How many cheques are stolen? How many share certificates do not reach people? The biggest newspapers in the country carry full-page advertisements in 'The Times of India' and 'The Indian Express' from time to time that the share certificates worth so many thousands of rupees each did not reach their destination. What is the explanation for it? I myself have been a victim in at least two cases of theft and the hon. Minister says that he is satified with the postal services. If he is satisfied with this thing, he will be satisfied with anything. I would like to know what the extent of these thefts is, how much it costs the people and how much it costs the Government. The way the postal department is working, it is a shameful thing.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् माननीय सदस्य ने शुरु में कहा कि परसेंटेज से हम संतुष्ट नहीं हैं, कितनी कंपलेंट्स हुई, यह इनको मालूम होना चाहिये। अनरजिस्टर्ड मेल में 1328 करोड़ सेवाएं हुई जिसमें 16 हजार कंपलेंट्स मिलीं, परसेंटेज है .009 परसेंट। रजिस्टर्ड मेल में 32 करोड़ 23 लाख सेवाएं हुई और कंपलेंट्स है 3 लाख 88 हजार और परसेंटेज हुई 1204। इसी तरह से मनी आर्डर की 10.1 करोड़ सेवाएं हुई और कंपलेंट्स मिली 2 लाख 67 हजार, परसेंटेज हुई .27। रजिस्टर्ड पार्सल की 313 लाख सेवाएं हुई 24 हजार कंपलेंट्स आई, परसेंटेज हुआ .077। इसके इलावा अगर कोई स्पेसेफिक शिकायत है तो आप हम को लिख कर भेज दें, हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे और यदि कहीं विभाग की गलती होगी..**(व्यवधान)**

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, रजिस्टर्ड पार्सल गायब हो जाते हैं। **(व्यवधान)** बहुत बड़ी संख्या है 24000..

SHRI K.R. MALKANI: Sir, that is not my point ..*(interruptions)*...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदय, दो दो सदस्य बोल रहे हैं

MR. CHAIRMAN: Let the Minister complete his reply...*(interreuptions)* ...Let him complete.

SHRI K.R. MALKANI: Sir, my point is very defferent. I complained twice. Then I was told, "Shall we send you one hundred rupees? Shall we send you five

hundred rupees?" Nobody Cares for one hundred rupees or five hundred rupees. Why should the articles get lost in transit?--that is the point. The objection is to the fact of theft and the hon. Minister is taking it lightly. I would like to know the amount that is lost, and the loss that the Indian Postal Department suffers as a result of these thefts. If you don't have the figures, please find them out and let us know. You have talked of your 10-Point Programme. Please let us know what those ten points are....*(interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: And it can't be explained in percentages ...*(interruption)*... Mr. Chairman, it can't be explained in percentages.

इतना बड़ा शरीर है और दो इंच का हार्ट है **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Have you got the information readily available? ....(interruptions)...Have you got the **inforamtion** readily available, the amount of loss?

श्री सतीश अग्रवाल: इतना बड़ा शरीर, दो इंच का हार्ट है, आप कहें हार्ट इज़ डेमेज्ड,

Then you will say '.001 per cent is dead'.

SHRI BENI PRASAD VARMA: You have asked the percentage of complaints.

SHRI K.R. MALKANI: I have not asked the percentge. I have asked the absolute figures.

परसेंटेज तो आप रिपीट करते रहे **(व्यवधान)**

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: He whats the absolute figures.

उन्होंने एब्सोल्यूट फिगर्ज़ मांगी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैंने पूरा आंकड़े बता दिये हैं। आप संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। श्रीमन् यह आवश्यक नहीं है कि माननीय सदस्य जिस प्रकार का उत्तर चाहे उसी प्रकार का उत्तर सरकार की ओर से आ जाए। आपके प्रश्न का जो आशय है, उसका उत्तर हम दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: जो पूछा जाए उसका उत्तर आप नहीं देंगे? **(व्यवधान)** जो पूछा गया है क्या आप अपनी इच्छा के मुताबिक उत्तर देंगे? **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: **Sir,** this is not the Zero Hour....*(interruptions)*... Sir, this is not the Zero Hour. This is Question Hour....*(interruptions)*...This is not Zero Hour.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् यदि एक साथ सब लोग प्रश्न करने लगेंगे तो मैं उन सब का उत्तर कैसे दे पाऊंगा। आप हमारी सहायता कीजिये। **(व्यवधान)** अपोज़ीशन फार दी सेक आफ अपोज़ीशन नहीं होना चाहिये। **(व्यवधान)**

SHRI K.R. MALKANI: Sir, this is objectionable. This is absolutely objectionable. He said, 'Opposition for the sake of opposition'. I would like to know the amount that the Postal Department losses through thefts. If he does not have a ready reply, he can come later with a reply...*(interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If the amount is not readily available, the hon. Minister can assure them that he will give the information later...*(interruptions)*...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् आपका आदेश तो हम मानेंगे ही लेकिन यह स्पेसेफिक सवाल था डाक सेवाओं में सुधार के लिए। कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कर लें। चाहें तो मैं अलग से सूचना भी उनको दे दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: अलग से कैसे जवाब देंगे? जो जवाब देना है वह सदन मे देना है और पूरे सदन के लिए है। किसी की पर्सनल प्रापर्टी नहीं है। सवाल-जवाब दोनों पूरे हाऊस के लिए है **(व्यवधान)**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: मैंने यह अनुरोध किया है अलग से सवाल कर लें। श्रीमन् मनी आर्डर सेवाओं में नुकसान का प्रश्न पैदा होता है मुख्य रूप से मनी आर्डर का न मिलना। मनी आर्डर अगर मिस होता है जिसको पहुंचना है उसको शिकायत होती है तो 10-15 दिन में थोडी सी जांच कर के उसको पैसा दे देते हैं। लेकिन जो विभाग को नुकसान होता है उनकी जांच कर के उससे रिक्वरी भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उसके आंकड़े ही जानना चाहते है कि कितना उनको नुकसान होता है तो आप अलग से सवाल कर लें वह बेहतर होगा।

MR. CHAIRMAN: Question No.22, Shri Ajit Jogi.

SHRI K.R. MALKANI: Sir, ...(*Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: We have taken 20 minutes for the this question. *(Interruptions)*... We have taken 20 minutes already for this question. Mr. Jogi.

उन्नत परमाणु रिएक्टरों का निर्यात

*22. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूरेनियम और थोरियम संजातों का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले अनेक प्रकार के उन्नत परमाणु रिएक्टरों का निर्यात करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने यह प्रस्ताव पहली बार किया है;

(ग) किन-किन देशों ने इन परमाणु रिएक्टरों को खरीदने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) क्या इन देशों के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इन रिएक्टरों का उपयोग केवल अनुसंधान के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) India had sometime ago offered a nuclear research reactor of an advanced design for export under the safeguards of International Atomic Energy Agency (IAEA).

(c) to (e) In response to an invitation from Thailand for making pre-qualification bid, India had submitted relevant information and an offer for setting up a research reactor. However, India was not among the bidders short-listed for giving the final quotation. Since the offer was only as a pre-qualification bid, the question of signing any agreement did not arise.

(f) Does not arise.

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि विकासशील देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जो परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए पूरी तरह से आत्म निर्भर है। यह भी बड़ी खुशी की बात है कि पूरी दुनिया में केवल दो देश ऐसे हैं जो थर्ड जनरेशन ब्रीडर रिएक्टर बना सकते हैं और उनमें से भारत एक है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि हमने अब इस टेक्नालाजी को एक्सपोर्ट करने की दिशा में कदम उठाया है। थाइलैंड को हमने आफर दिया है और मंत्री महोदय ने बताया कि वह मंजूर नहीं हो पाया है। पर यह अच्छी बात है। इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब हम परमाणु रिएक्टर बनाने के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए हैं तो क्या कारण है कि हम परमाणु ऊर्जा इतनी कम देश के अंदर बना रहे हैं। हर देश में एक आदर्श अनुपात होना चाहिए थर्मल पावर का, हाइडिल पावर का, न्युक्लियर पावर का। वह अनुपात हमारे देश में क्या है और उसमें से जो न्युक्लियर पावर हमको बनानी चाहिए उतनी हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ढाई सौ-तीन सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष इस पर अलाट होने चाहिए। 50—60 करोड़ रुपया हम क्यों खर्च कर रहे हैं। इस बारे में मंत्री जी प्रकाश डालें।

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Sir, I am grateful to the hon. Member for the compliments that he has paid to our research scientists. The reactor that has been discussed in terms of export is, of course, a research reactor which is basically used for research purposes. As far as the power plants are concerned, we do have a programme for construction and that programme is going apace. The hon. Member may recall that, as far as the nuclear power stations are concerned, we are in a phase of erecting and commissioning 500-megawatt power stations and there have been some problems in capacity utilisation of some of the earlier power stations which are being attended to.

SHRI AJIT P. K. JOGI: My question was different, Sir. What I asked was that there is an ideal proportion between thermal, hydel and nuclear power. What is it for India? Why are we not producing that much of power in the nuclear sector? We have the technology; we have the resources and nuclear power is one of the